भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4009
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

4009. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या 'एक देश, एक समय' तंत्र को आंध्र प्रदेश में पत्तनों, विद्युत कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार अवसंरचना और डिजिटल बैंकिंग तंत्र में कार्यान्वित किए जाने का विचार है और यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और प्रस्तावित वित्तपोषण सहायता क्या है;
(ख) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पत्तन सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना की 'व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी' पर आधारित भारतीय मानक समय तुल्यकालन प्रणाली को अपनाने की तैयारी का आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को पुरानी समय और तुल्यकालन अवसंरचना का उन्नयन करने में सहायता के लिए कोई वित्तीय सहायता का विशिष्ट योजना लाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या महत्वपूर्ण अवसंरचना में विदेशी जीपीएस-आधारित समय प्रणाली पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों का आकलन किया गया है और उनसे निपटने के उपाय सुझाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या आंध्र प्रदेश के लिए, विशेषकर डिजिटल पेमेंट, संभारतंत्र, पत्तनों और औद्योगिक गलियारों, आर्थिक और परिचालन संबंधी लाभों का अनुमान लगाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ): देश भर में भारतीय मानक समय (आईएसटी) प्रसार परियोजना को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से "एक राष्ट्र, एक समय" की दृष्टि के तहत भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए एक सुरक्षित और स्वदेशी फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है।

इस परियोजना में पांच क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) के माध्यम से दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय बाजार, ऊर्जा, बंदरगाह और अन्य डिजिटल अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आईएसटी के प्रसार का प्रावधान है।

प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल (पीटीपी) आधारित व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यूटीसी (एनपीएलआई) से ट्रेस किये जाने वाले आईएसटी के सुरक्षित प्रसार का एक सफल प्रदर्शन किया गया है जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), चेन्नई के साथ वैधीकरण भी शामिल है।

आंध्र प्रदेश के संगठनों सहित प्रयोक्ता संगठनों द्वारा फ्रेमवर्क को अपनाना, परिचालन अपेक्षाओं और संबंधित हितधारकों द्वारा कार्यान्वयन के अधीन है। इस परियोजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग से कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है।

स्वदेशी समय प्रसार फ्रेमवर्क, विदेशी जीएनएसएस-आधारित टाइमिंग स्रोतों पर निर्भरता को कम करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, महत्वपूर्ण अवसंरचना की विश्वसनीयता में सुधार करने और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश सहित देशभर में डिजिटल भुगतान, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों, दूरसंचार, ऊर्जा और उद्योग जैसे क्षेत्रों को दीर्घावधि लाभ प्रदान करना है।

*****